राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
बिहार लोक भवन, पटना–800022

प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या–165/2026

बिहार लोक भवन में शैक्षणिक अभिलेखों के डिजिटल अपलोड की समीक्षा की गई

पटना 21 अगस्त, 2026 :– राज्य के 17 विश्वविद्यालयों के लंबित डिग्री, अंकपत्र और अन्य शैक्षणिक अभिलेखों को 30 सितंबर, 2026 तक राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार (National Academic Depository-NAD) एवं शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (Academic Credit Bank-ACB) पोर्टल पर अपलोड किये जाएँगें। यह निर्णय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया।

बैठक में विश्वविद्यालयवार अपलोड की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। विश्वविद्यालयों की प्रगति की समीक्षा अब हर 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक अभिलेखों के अपलोड की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी।

बिहार के पुराने शैक्षणिक अभिलेखों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार एवं शैक्षणिक क्रेडिट बैंक के राष्ट्रीय समन्वयक ने बताया कि बिहार की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लंबित अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अपलोड के लिए पोर्टल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक पुनः खोला जाएगा।

बैठक में बताया गया कि पुराने हस्तलिखित और कागजी अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में बदलने के लिए विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे।

पुराने अंक–आधारित अभिलेखों को एक समान तरीके से अपलोड करने के लिए साझा प्रारूप तैयार किया जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मिलकर इस प्रारूप को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद इसे सभी संबंधित विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों को तकनीकी सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय में एक आईटी प्रबंधक उपलब्ध कराया जाएगा। वे अभिलेखों के डिजिटलीकरण, अपलोड, निगरानी और तकनीकी समस्याओं के समाधान में विश्वविद्यालयों की मदद करेंगे।

आगे पृष्ठ 2 पर.....

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शैक्षणिक अभिलेखों का डिजिटल रूप में उपलब्ध होना विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को अपनी डिग्री, अंकपत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र कहीं से भी आसानी से और शीघ्र प्राप्त करने एवं सत्यापित कराने की सुविधा मिलेगी, जिससे उच्च शिक्षा, रोजगार और विदेश में अध्ययन के अवसरों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार के समन्वयक, एनएडी–एबीसी के राष्ट्रीय समन्वयक श्री प्रकाश कुमार पाण्डेय एवं उच्च शिक्षा विभाग व बिहार लोक भवन के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

.....